Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

16 नवंबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 11 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 प्रधानमंत्री मोदी 17 नवंबर 2026 को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनीला रवाना

PM Modi leaves for Manila to attend the 23rd ASEAN-India Summit and the 21st East Asia Summit on 17 November 2026

SSC • Banking • Railway • General

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर 2026 को अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर 17 नवंबर 2026 को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस के मनीला की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के केंद्र में हैं और 'महासागर' विजन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये संबंध व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जन-जन के बीच संबंधों तक फैली एक गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वे अन्य नेताओं के साथ मिलकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, जबकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर संवाद का मंच है, जहां वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। वे फिलीपींस में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। इस यात्रा पर प्रधानमंत्री कार्यालय की एक पूर्व रिलीज़ में बताया गया था कि ये शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आसियान के अध्यक्ष के रूप में फिलीपींस की मेज़बानी में हो रहे हैं, और भारत तथा आसियान 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336707

2 भारत और मिस्र ने पहली बार मंत्री स्तर पर 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की; वरीयता व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों पर विचार के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति

India and Egypt hold the 7th Joint Trade Committee at ministerial level for the first time; agree to set up a Joint Working Group to explore Terms of Reference for a Preferential or Free Trade Agreement

SSC • Banking • Railway • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। यह पहला मौका था जब इस द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर हुई। बैठक के एक प्रमुख परिणाम के रूप में दोनों मंत्री वरीयता व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने 12 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समिति ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की, जो वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025–मार्च 2026) में 35% बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया; अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान व्यापार बढ़कर 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह 3.08 अरब अमेरिकी डॉलर था। श्री गोयल ने पूरकता के पाँच क्षेत्र बताए: औषधि और स्वास्थ्य सेवा; इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल; कृषि और खाद्य प्रसंस्करण; डिजिटल और फिनटेक; तथा संस्कृति और संग्रहालय, जिसमें ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम और भारत के आगामी युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच प्रस्तावित सहयोग शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में या पारस्परिक सुविधा के अनुसार उससे पहले नई दिल्ली में होगी। भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में भारत और मिस्र की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, और भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की 6वीं बैठक भी हुई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336726

3 अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 12.29% हुई, सितंबर में 11.39% थी; ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 32.84%

WPI inflation rises to 12.29% in October 2026, from 11.39% in September; Fuel and Power inflation at 32.84%

SSC • Banking • Railway • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2022-23) पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.29 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर 2026 में यह 11.39 प्रतिशत थी। सभी वस्तुओं का सूचकांक 113.3 रहा, जो सितंबर में 112.5 था। तीन प्रमुख समूहों, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पाद, की मुद्रास्फीति क्रमशः 9.24 प्रतिशत, 32.84 प्रतिशत और 9.54 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह क्रमशः 8.67 प्रतिशत, 25.85 प्रतिशत और 9.76 प्रतिशत थी। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.99 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति 8.58 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.66 प्रतिशत थी। अक्टूबर में मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले कारकों में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं और मूल धातुएं शामिल थीं। अगस्त 2026 का अंतिम सूचकांक 110.8 पर अपरिवर्तित रहा, और अगस्त की थोक मुद्रास्फीति दर भी 9.92 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। अक्टूबर का अनंतिम सूचकांक 81.1 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के आधार पर तैयार किया गया। नवंबर 2026 के आँकड़े सोमवार, 14 दिसंबर 2026 को जारी होंगे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336762

4 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की तकनीक को टीआरएल-5 से टीआरएल-9 तक ले जाने के लिए आरडीआई कोष के तहत हैदराबाद की नियो सीकरमेटल्स के साथ समझौता किया

Technology Development Board signs agreement with Hyderabad's Neo Seekermetals under the RDI Fund to take critical-metal recovery from e-waste and lithium-ion battery waste from TRL-5 to TRL-9

SSC • Banking • Railway • General

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष के तहत तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मेसर्स नियो सीकरमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। 'ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण से महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण' नामक इस परियोजना की कुल लागत ₹20 करोड़ है, जिसमें से ₹10 करोड़ आरडीआई कोष के तहत स्वीकृत किए गए हैं, और यह वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट, ओसीडी) के रूप में दी जाएगी। कंपनी की एकीकृत और पेटेंट प्राप्त पुनर्चक्रण प्रक्रिया ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे, दोनों को संसाधित कर मूल्यवान धातुएं और बैटरी सामग्री प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। परियोजना का लक्ष्य इस तकनीक को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल)-5 से टीआरएल-9 तक ले जाकर व्यावसायिक स्तर पर उपयोग की ओर बढ़ाना है। टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर भारत के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच आवश्यक होगी, और ई-कचरे तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से इन्हें प्राप्त करने की स्वदेशी क्षमता विकसित करना इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336782

5 रक्षा मंत्रालय (रक्षा संपदा महानिदेशालय) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Ministry of Defence (DGDE) and Ministry of Social Justice and Empowerment sign MoU to set up and strengthen Day Care Centres and Senior Citizen Homes in Cantonment areas under AVYAY

SSC • Railway • Banking • General

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए सहायता शामिल है, और समझौता ज्ञापन में इस योजना के तहत छावनियों में नए डे केयर केंद्र या वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ छावनियों की पहचान की है: बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। पाँच छावनियों (अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन) के मौजूदा डे केयर केंद्रों और दो छावनियों (अयोध्या और लखनऊ) के वरिष्ठ नागरिक गृहों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड उपयुक्त परिसर और आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और परिचालन सहायता देगा। 12 छावनियों में और उनके आसपास रहने वाले युवाओं को वृद्धजन देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह इस पहल के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी का काम करेगा। यह समझौता ज्ञापन ऐसे समय हुआ है जब रक्षा संपदा विभाग 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मना रहा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336804

6 गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना शुरू; वहां घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी

Self-Enumeration for Phase II of Census 2027 begins in Goa, Punjab, Uttar Pradesh and the non-snow-bound areas of Uttarakhand; house-to-house Population Enumeration there from 1 December 2026 to 4 January 2027

SSC • Railway • Banking • General

गृह मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना (पीई), के लिए स्व-गणना (एसई) की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 को गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में शुरू हो गई। इन राज्यों और क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर 2026 तक अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहां घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा, और इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 को 00:00 बजे होगी। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी और जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा; वहां संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे होगी। पहले चरण के अंतर्गत मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। रिलीज़ के अनुसार जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल उपकरणों से की जा रही है और इसमें स्व-गणना को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया गया है: यह 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध एक वेब-आधारित सुविधा है, जिसमें निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर (प्राथमिकता से पहले चरण के दौरान पंजीकृत नंबर) से लॉग इन करके परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विवरण सफलतापूर्वक जमा करने पर एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) बनती है, जिसे प्रगणक के घर आने पर उनके साथ साझा करना होता है। प्रगणक सभी आवंटित ब्लॉकों में घर-घर जाना जारी रखेंगे, और जो परिवार स्व-गणना का विकल्प नहीं चुनते, उन्हें इन्हीं दौरों में शामिल किया जाएगा। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजना के लिए किया जाता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337054

7 अक्टूबर 2026 का पीएलएफएस मासिक बुलेटिन: बेरोजगारी दर घटकर 4.9%, श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 55.7% और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 35.0% हुई

PLFS monthly bulletin for October 2026: unemployment rate falls to 4.9%, labour force participation rises to 55.7% and female LFPR to 35.0%

SSC • Banking • Railway • General

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 16 नवंबर 2026 को अक्टूबर 2026 का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) मासिक बुलेटिन जारी किया, जो मासिक और तिमाही अनुमान देने के लिए जनवरी 2025 से सर्वेक्षण पद्धति में बदलाव के बाद की श्रृंखला का उन्नीसवां बुलेटिन है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पद्धति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई, जो सितंबर 2026 में 5.0 प्रतिशत और अक्टूबर 2025 में 5.2 प्रतिशत थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) सितंबर के 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले यह 55.4 प्रतिशत थी); इस सुधार में ग्रामीण क्षेत्र आगे रहे, जहां यह दर 58.0 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी एलएफपीआर 50.5 प्रतिशत रही। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 52.7 प्रतिशत से बढ़कर 53.0 प्रतिशत हो गया, जो फरवरी 2026 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 34.6 प्रतिशत से बढ़कर 35.0 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी 2026 के बाद इसका भी उच्चतम स्तर है, और महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गया। महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत से घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई; ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत रही, जो 2026 के दौरान दर्ज इसका सबसे निचला स्तर है, और शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही। ये अनुमान कुल 3,70,475 सर्वेक्षित व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,11,474 और शहरी क्षेत्रों में 1,59,001) से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336905

8 भारत और थाईलैंड ने नोंथाबुरी में संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक की; वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 12.6% बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा

India and Thailand hold the 14th Joint Trade Committee meeting in Nonthaburi; bilateral trade grew 12.6% to USD 21.49 billion in FY 2025-26

SSC • Banking • Railway • General

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 14वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित वाणिज्य मंत्रालय में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक सुश्री चोतिमा इअमसवासदिकुल ने की। दोनों पक्षों ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा; रिलीज़ के अनुसार आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा 16.7 प्रतिशत रहा। भारत ने अवसंरचना और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स), मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), तथा पर्यटन, आतिथ्य और आरोग्य (वेलनेस) क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर ज़ोर दिया, जबकि थाईलैंड ने अपना 'सह-सृजन, सह-निवेश' (को-क्रिएशन को-इन्वेस्टमेंट) दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिस पर भारत ने आगे विचार करने पर सहमति जताई। बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) और भारत-थाईलैंड शीघ्र लाभ योजना (अर्ली हार्वेस्ट स्कीम) के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों और वरीयताओं के उपयोग से जुड़े आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान के तंत्र पर विचार किया गया, और एआईटीआईजीए की समीक्षा के शीघ्र और सार्थक निष्कर्ष के महत्व पर ज़ोर दिया गया। कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (एसपीएस) उपायों तथा गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ना, स्थानीय मुद्रा में निपटान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में होगी।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337121

9 भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास आईएमएनईएक्स-26 का 8वां संस्करण बंदरगाह और समुद्री चरणों के बाद विशाखापट्टनम में संपन्न

8th edition of the India–Myanmar Naval Exercise, IMNEX-26, concludes at Visakhapatnam after its Harbour and Sea Phases

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (आईएमएनईएक्स-26) का 8वां संस्करण अपने बंदरगाह चरण और समुद्री चरण के सफल समापन के बाद 14 नवंबर 2026 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। बंगाल की खाड़ी में हुआ समुद्री चरण इस अभ्यास का परिचालन संबंधी समापन चरण था, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाजों आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा ने म्यांमार नौसेना के जहाज यूएमएस किंग सिन फ्यू शिन के साथ मिलकर समन्वित समुद्री युद्धाभ्यास और परिचालन अभ्यास किए, ताकि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके, सामरिक समन्वय बढ़े और अंतर-संचालनीयता मज़बूत हो। बंदरगाह चरण में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई), एक-दूसरे के जहाजों के दौरे, पेशेवर संवाद और खेल गतिविधियां शामिल थीं। मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास भारत के 'महासागर' (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) विजन और 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336938

10 नई दिल्ली में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र आयोजित; दोनों पक्षों ने 2027–2031 के लिए सहयोग के मार्गचित्र (रोडमैप) पर चर्चा की

12th Session of the India–Belarus Inter-Governmental Commission held in New Delhi; both sides discuss a Roadmap for Cooperation for 2027–2031

SSC • Banking • Railway • General

भारत-बेलारूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम रिझेनकोव ने बेलारूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सत्र में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और व्यापार, आर्थिक तथा निवेश संबंधों को और मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने की दिशा में एक कदम के रूप में 2027–2031 के लिए सहयोग के मार्गचित्र (रोडमैप) पर चर्चा की, और जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें उद्योग, वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, निर्माण तथा सीमा शुल्क सहयोग शामिल थे। 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर दोनों सह-अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। सत्र के साथ-साथ उसी दिन नई दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार और निवेश मंच (बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम) का आयोजन भी हुआ, जिसमें मोटर वाहन और कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, औषधि, रसायन, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की बेलारूसी कंपनियों ने भाग लिया; कृषि और नागरिक मानवरहित हवाई प्रणालियों, औषधि सहयोग, खनन उपकरण, जल शोधन प्रौद्योगिकियों और खाद्य प्रसंस्करण को भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया। व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कारोबारियों को संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी साझेदारियों और निवेश के अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों पक्ष आयोग का 13वां सत्र 2027 में आयोजित करने पर सहमत हुए, जिसकी तारीख़ें और कार्यसूची राजनयिक माध्यमों से तय की जाएंगी।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337070

11 देवेश चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और कमोडोर (सेवानिवृत्त) पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया

Devesh Chaturvedi assumes office as Chairperson and Commodore (Retd.) Pushpendra Kumar Garg as Member of the National Sports Board

SSC • Railway • Sports • General

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) के नए नेतृत्व ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पदभार ग्रहण किया। श्री देवेश चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने एनएसबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जबकि कमोडोर (सेवानिवृत्त) पुष्पेंद्र कुमार गर्ग एनएसबी के सदस्य बने। एनएसबी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंज़ूरी दी है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत हुई है और इसे राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमावली, 2026 के माध्यम से क्रियाशील बनाया गया है। रिलीज़ के अनुसार यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत के शीर्ष केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337047

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ हुए जिस समझौते की घोषणा 16 नवंबर 2026 को की गई, उसके तहत ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की नियो सीकरमेटल्स की परियोजना के लिए आरडीआई कोष के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(A) ₹5 करोड़
(B) ₹50 करोड़
(C) ₹20 करोड़
(D) ₹10 करोड़

प्र.2 देवेश चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने 16 नवंबर 2026 को किस निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया?

(A) राष्ट्रीय खेल बोर्ड
(B) राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण
(C) भारतीय खेल प्राधिकरण
(D) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी

प्र.3 16 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय (रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाएगी?

(A) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
(B) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)
(C) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)
(D) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

प्र.4 गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में, जहां 16 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना शुरू हुई, जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि (00:00 बजे) क्या होगी?

(A) 1 दिसंबर 2026
(B) 1 मार्च 2027
(C) 30 नवंबर 2026
(D) 5 जनवरी 2027

प्र.5 नवंबर 2026 में मंत्री स्तर पर सह-अध्यक्षता में हुई भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके लिए कितने का लक्ष्य रखा गया है?

(A) 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर
(B) 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर
(C) 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर
(D) 12 अरब अमेरिकी डॉलर

उत्तर: 1-(D) 2-(A) 3-(C) 4-(D) 5-(D)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।